उस समय भोजपुरी भाषा के बारे में भी उल्लेख किया था और यह कहा था कि करोड़ों लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं। क्या भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का आश्वासन आप दे सकते हैं?

श्री सभापति: इसके लिए अलग से प्रश्न होगा, आश्वासन देने का।

Subsidy on Import of wind power electric generating units/parts

*330. SHRIMATI AMBIKA SONI:††
SHRI SANTOSH BAGRODIA:

Will the Minister of NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether there is a subsidy on importing wind power electric generating units or their machinery parts;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether there are entrepreneurs in India who are indigenously manufacturing similar machines in India;

(d) if so, the comparative details of the cost of an imported wind power unit to a similar KV unit manufactured in India; and

(e) whether Government have plan to remove the subsidy offered on import of such machines or equipment?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI VILAS MUTTEWAR): (a) and (b) There is no subsidy on importing wind power electric generating units or their machinery parts.

(c) No, Sir. However, wind electric generators are being produced through local production in the country, using some imported sub-systems, components and raw materials.

(d) As complete machines are not being imported, their price cannot be compared with indigenously produced machines.

---

††The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Ambika Soni

(e) Does not arise.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether a study has been done with regard to the generation of wind power. How does it compete financially, in terms of investment with thermal and hydro-power? If the wind power is advantageous, then, are we using it to the full potential?

श्री विलास मुत्तेमवार: जहां तक पवन बिजली का सवाल है और इसकी तुलना थर्मल और बाकी मदों से की गई है, तो पवन ऊर्जा की लागत चार करोड़ आती है और थर्मल की लागत भी चार करोड़ आती है। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में बड़े परिणाम में विनिवेश हुआ है और करीब दस हजार करोड़ का इसमें इनवेस्टमेंट हुआ है और 2500 का जेनरेशन विंड पावर में हुआ है।

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, my second supplementary is this. I read this morning in a section of the press that people are being given tax incentives to invest in companies involved in wind power electric generation. In the reply given to us, the hon. Minister has said that so far no incentive, no subsidy is being given to anyone producing these machineries whether wholly or partly in India. I want to know if this is an alternative source of non-conventional energy and competes with the other sources, then, what is holding the Government back to give tax incentive or other incentives to those who produce those machineries indigenously, instead of always importing them from outside.

श्री विलास मुत्तेमवार: जैसा कि मैंने अपने जवाब में कहा है कि पवन विद्युत उत्पादन युनिटों पर या मशीनी कलपुर्जों के आयात पर कोई सबसिडी नहीं दी जाती - ऐसा सवाल पूछा गया है, लेकिन देश में पवन विद्युत जेनरेटरों का निर्माण स्थानीय उत्पादन के माध्यम से किया जा रहा है, जिनमें कुछ आयातित उपप्रणालियों पर, संघटकों और कच्ची सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, उस पर रियायती सीमा शुल्क दिया जाता है तथा राजकोषीय लाभ जैसे 80 प्रतिशत त्वरित अवमूल्यन व करावकाश आदि दिये जाते हैं और जहां तक उसको बढ़ावा देने का सवाल है, तो राज्य सरकारों ने अपने-अपने ढंग से इस विंड एनर्जी में इनवैस्टमेंट करने के लिए तथा उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने तौर पर बहुत से कंसेशन दिए और उसका लाभ उन राज्यों में विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए विंड और जेनरेशन करने के लिए हुआ है।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has made any study as to

which are the States where wind power can be used, because this is an eco-friendly power which can be produced in remote areas, border areas and then the villages, which are not accessible otherwise, can be given power from those areas. Has the Government made any study on this? Does the Government plan to make this study as to which are the places where it can develop this kind of power; and also does the Government plan to have any special fund so that this eco-friendly power can be generated more?

श्री विलास मुत्तेमवार: पूरे देश में 45000 मेगावाट विंड पावर से जेनरेट करने का पोटेंश्यिल assess हुआ है और जो मुख्य राज्य हैं जिनमें विंड पावर जेनरेट करने का पोटेंश्यिल है, वे हैं महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। आज 2500 मेगावाट के करीब इस क्षेत्र में जेनरेशन हुआ है, और ज्यादा पोटेंश्यिल इसमें है। अगर हम तीन साल के आंकड़े देखेंगे, मैं सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा कि उसमें बड़ी प्रगति हुई है। सन् 2002 में 288 मेगावाट, 2003 में 242 मेगावाट, मार्च 2004 तक 615 मेगावाट उत्पादन हुआ है और इस वर्ष से 2005 तक करीबन 800 से 1000 मेगावाट पावर की हम अपेक्षा करते हैं। इस क्षेत्र में इंवेस्टमेंट और जनरेशन बहुत इनकीजिंग है। इसके साथ ही सदस्या महोदया ने इसको बढ़ावा देने के बारे में पूछा है तो बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों ने जहां पीपीए ठीक ढंग से दिया है, वहां पर लोग इस तरह के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। अब तो बड़ी कम्पनियों, बड़ी तादाद में इसमें इंवेस्टमेंट करने के लिए और विंड पावर से जनरेट करने के लिए इस क्षेत्र में आ रही हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, in regard to power generation from wind energy, the hon. Minister was pleased to visit the State of Pondicherry, where Suzan Company has been a pioneer. They are producing equipment for generating upto two megawatts of power; they are doing this indigenously, in India. The hon. Minister has visited the plant, too.

Now, as regards the companies that are manufacturing these equipment, in the 90s, subsidies were being given by the Government. Subsequently, a large number of wind power mills were set up. In Tamil Nadu, Kerela, Karnataka and Andhra Pradesh, areas have been identified to set up plants. And now, after a full, even though subsidies have not been given, to a certain extent, plants have been set up and power generation through wind has been started.

Now, the hon. Minister has said that the Government is giving subsidies only for certain items.

MR. CHAIRMAN: Please, put the question.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I am just coming to the question

Sir, one plant requires a minimum of one crore of rupees. ...*(Interruption)*... Therefore, I would like to know from the hon. Minister, for power generation....*(Interruption)*.... Would the hon. Minister review the decision of the Government and give subsidies, restore the subsidies, so that wind power can be utilized?

श्री विलास मुत्तेमवार: सभापति महोदय, मंत्रालय का काम renewable energy को generate जनरेट करने का, उसका promotion करने का, प्रचार और प्रसार करने का है। इस क्षेत्र में लोग आएं इसलिए पहले कुछ कंसेशन्स और रियायतें दी गई हैं। अब इस क्षेत्र में जिस तरह से लोगों का प्रवेश हो रहा है, जिस तरह से लोग इंवेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में अभी कहा है कि इस क्षेत्र में 2004 में 615 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। इस साल हम 800 से 1000 मेगावाट without subsidy achievement करने जा रहे हैं और जो कंसेशन राज्यों में दी है और जिस प्रकार कस्टम डयूटीज में रियायतें दी जाती हैं, उससे इस क्षेत्र में इंवेस्टमेंट हो रहा है और जनरेट भी हो रहा है।

डॉ फारुक अब्दुल्ला: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि लद्दाख क्षेत्र में हमें डीजल ले जाना पड़ता है और वह बहुत महंगा पड़ता है। वहां पर सर्दियों में पानी जम जाता है और जो हाइड्रो पावर है, वह भी काम नहीं करता है। एक इंस्टीट्यूशन के लिए हमने पहले भी गवर्नमेंट को अपील की थी, कि वहां पर विंड अनर्जी जनरेट की जा सकती है। उससे लोगों को फायदा हो सकता है। मैं आप से यह पूछना चाहता था कि क्या आपके पास कोई ऐसी स्कीम है कि लद्दाख के उन हिस्सों में और हमारे दूसरे इलाकों में, जहां हवा बहुत ज्यादा होती है, वहां विंड एनर्जी जनरेट की जाए। क्या इसके लिए आपके पास कोई स्कीमें हैं?

श्री विलास मुत्तेमवार: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि क्या हमारे पास ऐसी स्कीमें हैं तो हमारे पास ऐसी स्कीमें हैं। जहां हमें स्टेट गवर्नमेंट से ऐसी रिपोर्ट मिलती हैं कि वहां पर बड़ी तादाद में हवा चलती है तो डिमांस्ट्रेशन प्रोजेक्ट के नाम से हम खुद एक या दो मेगावाट का वहां प्रोजेक्ट लगाते हैं। यदि हमें अपेक्षित एचीवमेंट मिला और अगर वहां जनरेशन हुआ, तो फिर हम बाकी लोगों को वहां पर प्रोत्साहित करते हैं। हम वहां खुद अपनी योजनाएं कार्यान्वित करते हैं। जहां तक लद्दाख का सवाल है, उस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.